



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 जून, 1991/8 आषाढ़, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 1 अगस्त, 1990

सं० एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16)-13/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैण्ड (रेगुलेशन) (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 1986 (1986 का 16)” के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का

राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि)।

### हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1968

(1986 का 16)

(30-6-90 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश भूमि (अन्तरण) अधिनियम, 1968 (1969 का 15) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 8 का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन), 1968 (1969 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की विद्यमान धारा 8 को उक्त अधिनियम की उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित धारा के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (2) जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई न्यायालय जिसमें अपील या पुनरीक्षण अधिकारिता निहित है, या तो स्वप्रेरणा से या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा इसे दिए गए आवेदन पर अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति के पक्ष में किसी डिक्री के निष्पादन में उसकी सम्पत्ति की बिक्री को अपास्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि न्यायालय इस उप-धारा के अधीन, किसी आवेदन का संज्ञान करने से या उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से केवल इस कारण से ही इन्कार नहीं करेगा कि आवेदक या वह व्यक्ति प्रश्नगत सम्पत्ति जिसकी है, उस न्यायालय के समक्ष, जिसने या तो डिक्री पारित की है या उस निष्पादन की कार्यवाहियों में कोई आदेश पारित किया है, उस विस्तार तक आक्षेप करने में असफल रहा है।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 8-अ, इसके शीर्षक सहित, जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 8-अ  
का जोड़ना।

8-अ परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के अनुसूची में, जहां तक यह धारा 8 के अधीन कार्यवाहियों को लागू होता है, अनुच्छेद 65 के सामने द्वितीय स्तम्भ में आए शब्दों "बारह वर्ष" के पश्चात्, "किन्तु संविधान में (अनुसूचित जनजाति), आदेश, 1950 में हिमाचल प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी सदस्य की स्थावर सम्पत्ति की दशा में तीस वर्ष" शब्द, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।"

परिसीमा  
अधिनियम,  
1963 का  
जहां तक  
यह धारा 8  
के अधीन  
कार्यवाहियों  
को लागू  
होता है,  
संशोधन।

शिमला-2, 8 अक्टूबर, 1990

सं० एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16)-16/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश ऐवलिशन ऑफ लैण्ड रैवेन्यू आन अन्डकोनोमिक होल्डिंगज ऐक्ट, 1977 (1978 का 2)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-,  
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश अलाभकर जोत भू-राजस्व समाप्ति अधिनियम, 1977

(1978 का 2)

(31-8-90 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में अलाभकर जोत पर भू-राजस्व समाप्त करने का उपबन्ध करने  
के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठ्ठाइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अलाभकर जोत भू-राजस्व समाप्ति अधिनियम, 1977 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “भू-जोत से राज्य में किसी व्यक्ति के कब्जे में चाहे मालिक, बन्धकदार, पट्टेदार, अभिधारी के रूप में या किसी अन्य विधिपूर्ण हैसियत से, कुल भूमि और यदि ऐसा व्यक्ति अन्यो के साथ संयुक्त रूप से भूमि धारित करता है, तो ऐसी जोत में उसका भाग अभिप्रेत है ;

(ख) “अलाभकर भू-जोत” से ऐसी भू-जोत अभिप्रेत है जो अढ़ाई एकड़ से अधिक न हो और इसमें जोती हुई असंचित भूमि समाविष्ट है या ऐसी भूमि जिसे यथा, “बन्जर कदीम” “बन्जर जदीद” या चरागाह भूमि अभिलिखित किया गया है चाहे ऐसी भूमि को किसी भी नाम से अर्थात् “घासनी”, “खरेत”, “रूतास” आदि से पुकारा जाता हो, किन्तु उद्यानों के अधीन भूमि या भू-राजस्व के लिये निर्धारित निमित्त क्षेत्र इस के अन्तर्गत नहीं है ;

(ग) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में उनके हैं ।

अलाभकर भू-जोत पर भू-राजस्व की समाप्ति । 3. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, अलाभकर जोत पर भू-राजस्व रद्दी, 1977 से समाप्त हो जायेगा ; और, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर जो भू-स्वामी अलाभकर जोत धारित करता है, वह अपनी भू-जोत के बारे में सरकार को कोई भू-राजस्व देने का दायी नहीं होगा ।

कुछ अन्तरणों पर वर्जन । 4. (1) इस अधिनियम के प्रयोजन को विफल बनाने के लिए, जुलाई, 1977 के चौथे दिन के पश्चात् किए गए सभी भूमि अन्तरण, संघीय सरकार या राज्य सरकार को किए गए भूमि अन्तरण या किसी भू-स्वामी द्वारा सद्भावी अन्तरण या विधि के प्रवर्तन द्वारा किए गए भूमि के किसी अन्तरण के सिवाए, भू-धारक के राज्य को भू-राजस्व देने के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा ।

(2) जिले का कलैक्टर, जिसमें ऐसा अन्तरण होता है या होते हैं, यह अवधारित करेगा कि क्या अन्तरण सद्भावी है या नहीं और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

कठिनाईयों का दूर करने की शक्ति । 5. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो, राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित करवा कर या अन्यथा ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हो, जो इसे ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों ।

निरसन और व्यावृत्ति । 6. (1) हिमाचल प्रदेश अलाभकर भू-जोत भू-राजस्व समाप्ति अध्यादेश, 1977 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या करवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी, मानों कि उस दिन यह अधिनियम प्रवृत्त था जिस दिन ऐसी बात या करवाई की गई थी।

शिमला-2, 8 अक्तूबर, 1990

सं० एल०एल० आर० (राजभाषा)वी(16)-15/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश गुड कनडक्ट प्रिजनर (टेम्परेरी रिलीज) ऐक्ट, 1968 (1969 का 12)” क, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित  
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश सदाचरण बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1968

(1969 का अधिनियम संख्यांक 12)

8-4-1969

(1-7-1989 को यथा विद्यमान)

सदाचरण के लिए बन्दियों को कतिपय शर्तों पर अस्थाई रिहाई के लिए उपबन्ध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सदाचरण बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1968 है।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) "जिला मैजिस्ट्रेट" से उस जिले का जिला मैजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता में बन्दी इस अधिनियम के अधीन अस्थाई रिहाई के पश्चात् उसकी रिहाई की अवधि के दौरान सम्भाव्यता निवास करेगा ;
- (ख) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (ग) "बन्दी के कुटुम्ब का सदस्य" से बन्दी का पति, पत्नी, पुत्र-पुत्री, माता, पिता, भाई या बहिन अभिप्रेत है ;
- (घ) "अधिसूचना" से उचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में, प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;
- (ङ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (छ) "बन्दी" से करावास के दण्डादेश के अधीन कारागार में परिरुद्ध व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ज) "जेल अधीक्षक" से उस जेल का अधीक्षक अभिप्रेत है जिसमें बन्दी अपने कारागार दण्डादेश को भुगत रहा है।

कतिपय  
आधारों  
पर बंदियों  
की अस्थाई  
रिहाई।

3. (1) सरकार, जिला मैजिस्ट्रेट से परामर्श करके और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये किसी बन्दी को अस्थाई तौर पर रिहा कर सकेगी यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि,—

- (क) बन्दी के कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु हो गई है या सख्त बीमार है; या
- (ख) बन्दी के पुत्र या पुत्री का विवाह होना हो; या
- (ग) बन्दी की अस्थाई रिहाई उसकी भूमि पर हल चलाने, बीजने या फसल काटने या कोई अन्य कृषि कार्य करने के लिए आवश्यक है और उसकी अनुपस्थिति में, इस निमित्त, बन्दी का कोई भित्त या बन्दी के कुटुम्ब का कोई सदस्य उसकी सहायता करने के लिये तैयार नहीं है; या
- (घ) किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से ऐसा करना वांछनीय है।

(2) वह अवधि जिसके लिए बन्दी को रिहा किया जा सकेगा, सरकार द्वारा ऐसे अवधारित की जायेगी ताकि वह निम्नलिखित से अधिक न हो:—

- (क) जहां बन्दी को उप-धारा (1) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आधारों पर रिहा किया जाना है,—दो सप्ताह ;
- (ख) जहां बन्दी को उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) के अधीन रिहा किया जाना है,—चार सप्ताह ; और
- (ग) जहां बन्दी को उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन रिहा किया जाना है,—छः सप्ताह।

(3) इस धारा के अधीन रिहाई की अवधि, बन्दी को सकल दण्डादिष्ट अवधि में, गणित नहीं होगी।

- (4) सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं आधारों के सम्बन्ध में, इस धारा के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

4. (1) सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जिला मैजिस्ट्रेट के परामर्श से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, किसी बन्दी को अस्थाई तौर पर प्रावकाश पर, रिहा कर सकेगी, जिसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि का कारावास का दण्डादेश दिया गया है, और जो,—

प्रावकाश पर  
बंदियों को  
अस्थाई  
रिहाई।

(क) उसकी अस्थाई रिहाई की तारीख से ठीक पूर्व, छूट को अपवर्जित करके, तीन वर्ष की अवधि का कारावास भोग चुका है ;

(ख) ऐसी अवधि के दौरान कोई भी जेल अपराध नहीं किया है और कम-से-कम तीन वार्षिक सदाचरण छूटें अर्जित की हैं :

परन्तु इसकी कोई भी बात उस बन्दी को लागू नहीं होगी जो,—

(i) हिमाचल प्रदेश आभायासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित आभायासिक अपराधी है ; या

(ii) लूट या डकैती अथवा ऐसे अपराध के लिये जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सिद्धदोष ठहराया गया हो।

(2) प्रावकाश की अवधि, जिस के लिये बन्दी उप-धारा (1) के अधीन पात्र है, उसकी रिहाई के प्रथम वर्ष के दौरान तीन सप्ताह और उसके पश्चात् प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के दौरान दो सप्ताह होगी।

(3) धारा 8 की उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रिहाई अवधि, बन्दी के दण्डादेश की सकल अवधि में संगणित की जायेगी।

5. धारा 3 और 4 के अधीन बन्दी की अस्थायी रिहाई की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए कारगर से प्रस्थान और पहुंच के दिवसों का अपवर्जन किया जाएगा

धारा 3 और  
4 के अधीन  
अवधि की  
संगणना में  
कतिपय  
दिवसों का  
अपवर्जन।

6. धारा 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बन्दी इस अधिनियम के अधीन रिहाई के लिए, हकदार नहीं होगा, यदि, जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर सरकार या इस द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उसकी रिहाई इससे, सम्भाव्यता राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने में संकट हो सकता है।

कतिपय  
दशाओं में  
बंदियों का  
रिहाई के  
हकदार न  
होना।

निर्धन बंदियों के यात्रा व्ययों का सरकार द्वारा वहन किया जाना। 7. यदि, जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर सरकार का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन उसकी अस्थाई रिहाई के पश्चात् कारगार से और कारगार को, उसकी यात्रा के व्ययों को बन्दी का कुटुम्ब वहन नहीं कर सकता है, तो व्ययों का सरकार द्वारा ऐसी सीमा तक और रीति में जो विहित की जाए, वहन किया जाएगा।

रिहाई अवधि की समाप्ति पर अपने को प्रस्तुत करने का बन्दी का दायित्व और अधिक ठहरने के परिणाम। 8. (1) उप अवधि की समाप्ति पर, जिस के लिए इस अधिनियम के अधीन बन्दी को रिहा किया गया है, वह अपने को उस जेल के अधीक्षक को, जहां से उसे रिहा किया गया था, प्रस्तुत करेगा। (2) यदि कोई बन्दी उप-धारा (1) द्वारा या अपेक्षित रूप में उस तारीख से जिसकी उसे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए था, दस दिन की अवधि के भीतर अपने को प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसे दण्डादेश के अनवसित भाग को भुगताने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाएगा।

(3) यदि कोई बन्दी उस तारीख से, जिसकी उसे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए था, दस दिन की अवधि के भीतर, उस जेल के अधीक्षक के पास, जिससे उसे रिहा किया गया था, अपने को प्रस्तुत कर देता है, किन्तु जेल के अधीक्षक का इस बात से समाधान कराने में असफल रहता है कि वह उस अवधि को ठीक समाप्ति पर, जिसके लिए उसे रिहा किया गया था, अपने को प्रस्तुत करने में पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ था, तो बन्दी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई शास्ति, जेल के अधीक्षक द्वारा उसे दी जाएगी :-

- (क) अधिक ठहराव के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम पांच दिवसों की छुट्टी की कटौती ;
- (ख) अधिकतम एक मास की अवधि के लिए जलपान की रियायत का बन्द करना ;
- (ग) अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए साक्षात्कार या पत्रों या दोनों की रियायत का बन्द करना ;
- (घ) धारा 4 के अधीन प्रावकाश पर बन्दी की अस्थाई रिहाई की अवधि संगणना, उसके दण्डादेश में नहीं की जाएगी ;
- (ङ) चेतावनी ; और
- (च) "सिद्ध दोष चौकीदार" या "सिद्धदोष ओवरसियर" की हैसियत से और श्रेणी से अवनत करना।

अपने को प्रस्तुत करने में असफल रहने पर शास्ति। 9. कोई बन्दी जो धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन गिरफ्तार किए जाने के लिए दायी है, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में दण्ड बन्दी को उस अपराध में दिए गए दण्ड के अतिरिक्त है जिसमें सिद्धदोष किया गया है।



10. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेषतः, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना; ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,--

- (क) बन्दी द्वारा (उसके प्रतिभू सहित) रिहाई की अवधि के दौरान अच्छे आचरण और ऐसी अवधि के समाप्ति पर उसके अपने आनको प्रस्तुत करने के लिए बन्धपत्र का निष्पादन ;
- (ख) राशि जिस के लिए प्ररूप और रीति जिनमें ऐसा बन्धपत्र दिया जाएगा ;
- (ग) इसकी किसी शर्त के भंग की दशा में बन्धपत्र की राशि का समग्रहरण ;
- (घ) वे शर्तें जिन पर और रीति जिसमें बन्दी को इस अधिनियम के अधीन अस्थायी तौर पर रिहा किया जा सकेगा ;
- (ङ) वह रीति जिसमें बन्दी को रिहा करने से पूर्व जिला मैजिस्ट्रेट, से परामर्श किया जाएगा ; और
- (च) वह सीमा जिस तक और रीति जिसमें, सरकार द्वारा निर्धन बर्दियों के यात्रा व्ययों का वहन किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

11. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, पंजाब सदाचारी बन्द (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 (1962 का 11) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है : निरसन और व्यावृत्ति।

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है इस अधिनियम के अधीन की गई समझौ जाएगी।

शिमला, 8 अक्तूबर, 1990

सं० एल०एल०प्रार० (राजभाषा) बी (16)-17/90--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि हिमाचल प्रदेश विलेज कामन लैण्ड्स बैसटिंग एण्ड यूटिलाईजेशन ऐक्ट, 1974 (1974 का 18)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देता है। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त

अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलता भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974

(1974 का 18)

(31-7-90 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्राम शामिलता भूमि के निधान और उपयोग का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ । 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलता भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 है ।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएं । 2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "कलक्टर" से उस जिला का कलक्टर अभिप्रेत है, जिसमें सम्पदा स्थित है और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी जो सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी की पंक्ति से नीचे का न हो, भी इसके अन्तर्गत है,

(क क) "विकलांग व्यक्ति" से ऐसा अपंग या शारीरिक या चिकित्सकीय दृष्ट्यासे अपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको सभी स्रोतों से वार्षिक आय सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है, और जो, क्षति, बीमारी या जन्मजात विरूपता के कारण, सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है या उस कार्य के लिए जिसमें वह नियोजित है पूरी मजदूरी अर्जित करने या उस क्षति, बीमारी या विरूपता को ध्यान में रखते हुए नियोजन अभिप्राप्त करने या बनाए रखने या स्वयं ही ऐसा कार्य करने से सारभूत रूप से तिवारित है जो कार्य उस की आयु, अनुभव और अर्हताओं के अनूकूल होता ।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ऐसा व्यक्ति जो पचास प्रतिशत या अधिक शारीरिक निःशक्तता के परिमाण तक ग्रस्त है, सारभूत रूप से असमर्थ या निःशक्त व्यक्ति समझा जाएगा ;

(क क क) "गृहविहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास अपना कोई घर या स्वयं गृह निर्माण करने के लिए स्थल नहीं है :

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिस को पिता जीवित है या जिसकी सभी स्त्रोतों से आय तीन हजार रुपये से अधिक है, गृहविहीन व्यक्ति नहीं समझा जाएगा ;

(ख) "सम्पदा का निवासी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मामूली तौर पर सम्पदा में निवास करता है, चाहे वह स्वत्वधारी हो या गैर-स्वत्वधारी ;

परन्तु अस्थाई अनुपस्थिति या किसी दूसरी जगह नियोजन के संबंध में अनुपस्थिति, सम्पदा में उसके निवास को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ग) "भूमिहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो, कृषि प्रयोजनों के लिए स्वामी या अभिधारी के रूप में भूमि का धारक न होते हुए, भूमि में शारीरिक श्रम द्वारा मुख्यतः अपनी जीविका अर्जित करता है और कृषि व्यवसाय अपनाने का इरादा रखता है और व्यक्तिगत तौर पर खेती करने में समर्थ है ;

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसका पिता जीवित है या जिसकी सभी स्त्रोतों से आय तीन हजार रुपये से अधिक है, गृहविहीन व्यक्ति नहीं समझा जाएगा ;

(घ) "भू-स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका भू-अभिलेख में यथा अभिलिखित शामिलता भूमि में शेयर है और इसके अन्तर्गत पंचायत भी है ;

(घ घ) "अन्य पात्र व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, --

(i) जो, चाहे स्वामी या अभिधारी के रूप में कृषि प्रयोजनों के लिए एक एकड़ से कम भूमि धारित करता हो, और मुख्यतः भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करता है और कृषि का व्यवसाय करने का आशय रखता है और व्यक्तिक रूप से भूमि पर खेती करने में समर्थ है ;

(ii) जिसका पिता जीवित नहीं है ; और

(iii) जिसकी सभी स्त्रोतों से आय तीन हजार रुपये से अधिक नहीं है ; और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त स्वामित्वधीन या कृष्ट किसी सम्पदा का अंश या भाग धारित करता है ;

(ङ) "पंचायत" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "भूमि" और "निजीवन" शब्दों के वही अर्थ हैं जो उनके हिमाचल प्रदेश भूमि जोत अधिकृत्य सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का 19) में इन शब्दों के हैं ; और

(झ) इस अधिनियम में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ हैं जो ऐसे शब्दों और पदों के, यथास्थिति, पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का 17) या हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) में इनके हैं।

राज्य सरकार में अधिकारों का निहित करना। 3. (1) तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी करार, लिखित, रूढ़ि अथवा प्रथा या किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी सम्पदा की भूमि में, स्वामी के सभी अधिकार, हक और हित, जिसके अन्तर्गत समाश्रित हित, यदि कोई हों, भी हैं, जो —

(क) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब ग्राम शामिलता भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का 18) की धारा 4 के अधीन ग्राम पंचायत में निहित हैं, सिवाय ग्रामीण समुदाय के फयदे के लिए प्रयुक्त या आरक्षित भूमि के जिसके अन्तर्गत आबादी देह या गोरह देह में मार्ग, गलियाँ, खेल के मैदान, स्कूल पीने के पानी के कुएं अथवा तालाब भी हैं ;

(ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में, राजस्व अभिलेख में वर्णित शामिलता करफ, पट्टी, पाना और थोला और राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्रामीण समुदाय या उसके किसी भाग या ग्राम के सामान्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की गई है; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व समाविष्ट क्षेत्रों में राजस्व अभिलेख में वर्णित शामिलता, शामिलता देह, शामिलता टर्फ, शामिलता चैक और पट्टी ;

निर्वाचित हों जाएंगे ऐसे सभी अधिकार, हक और हित राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे जो सभी विल्लंगमों से मुक्त होंगे।

(2) इस अधिनियम की उप-धारा (1) के उपबन्ध, उस उप-धारा के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित भूमि पर लागू नहीं होंगे यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व —

(क) ऐसी भूमि का विभाजन व्यक्ति सह-भागदार द्वारा सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया से करवाया गया है ;

(ख) ऐसी भूमि का अन्तरण भू-स्वामी द्वारा विक्रय, दान या विनियम द्वारा किया गया है ;

(ग) किसी निवासी द्वारा आवासिक गृह या गोशाला का निर्माण करके निर्मित ऐसी भूमि।

(3) इस अधिनियम की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार संदाय करने की दायी होगी, और भू-स्वामी जिनके अधिकारी निर्वाचित हुए हैं, उसके स्थान पर निम्नलिखित दर पर रकम प्राप्त करने के हकदार होंगे —

(1) धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन चरागाह और अन्य

सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि के लिए, भूराजस्व का पांच गुणा जिसके अन्तर्गत उस पर प्रभार्य रेट और उपकर भी हैं; और

- (2) बाकि भूमि के लिए वार्षिक भू-राजस्व का पन्द्रह गुणा जिसके अन्तर्गत उस पर प्रभार्य रेट और उपकर भी हैं :

परन्तु जहां इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित भूमि का भू-राजस्व निर्धारित नहीं किया है वहां यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसे सम्पदा में उसी प्रकार की भूमि की तरह ही और अगर सम्पदा में उपलब्ध न हो तो साथ लगी हुई, यथास्थिति, सम्पदा या सम्पदाओं की तरह ही निर्धारित किया गया है।

(4) धारा 7 के अधीन पंचायत को संदत्त रकम को सभा निधि समझा जाएगा और इसका उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 40 में वर्णित हैं।

(5) भूमि के राज्य सरकार में निहित होने के पश्चात् किसी भी समय कलक्टर, लिखित आदेश द्वारा, भू-स्वामियों को आदेश की तामील क 10 दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए कब्जा परदत्त करने का निदेश दे सकेगा।

(6) यदि भू-स्वामी उप-धारा (5) के अधीन दिए गए आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करते हैं या युक्तियुक्त कारणों के बिना असफल रहते हैं, तो कलक्टर भूमि का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो।

4. (1) कलक्टर अपने जिला की पंचायतों से पंजाब ग्राम शामिलता भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का 18) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन पंचायतों में निहित भूमि के बारे में पंचायतों द्वारा दिए गए पट्टों, किए गए करारों और संविदाओं के अभिलेख को मंगवा सकेगा और अपने समाधान के लिए ऐसे पट्टों, संविदाओं या करारों की वैधता या औचित्य का परीक्षण कर सकेगा।

पंचायतों द्वारा दिए गए पट्टों पर व्यवहार।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन अभिलेख का परीक्षण करने और ऐसी जांच करने पर जैसी वह उचित समझे, कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसे पट्टे, संविदाएं या करार, उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार हैं, वह आदेश द्वारा यह घोषणा करेगा कि ऐसे पट्टों, संविदाओं या करार, राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं।

(3) जहां ऐसे परीक्षण और जांच पर कलक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पट्टा संविदा या करार उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में या कपट अथवा तथ्यों के छिपाए जाने के परिणाम स्वरूप किया गया है या भू-सम्पदा के अधिकार धारकों के अहित में हैं, वह ऐसे पट्टे, संविदा या करार को रद्द कर देगा और ऐसा व्यक्तिगत पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का 17) की धारा 150 के उपबन्धों के अधीन बेदखली का दायी होगा :

परन्तु इस धारा की उप-धारा (2) और (3) के अधीन कलक्टर द्वारा, पट्टे संविदा या करार के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा।

राज्य सरकार में निहित भूमि पर अधिकरणों पर व्यवहार। 5. जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या बाद में राज्य सरकार में निहित भूमि पर पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का 17) की धारा 150 या हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 163 के उपबन्धों के अनुसार स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति को, बेदखल कर सकेगा।

भू-स्वामियों को संदेय रकम का अवधारण। 6. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पश्चात् कलक्टर, विहित प्ररूप और रीति में भू-स्वामी को जिनके अधिकार, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन निर्वापित हुए हैं, नोटिस जारी करेगा, जिसमें राज्य सरकार में निहित भूमि क्षेत्र, और उसके लिए प्रस्तावित राशि को दर्शाएगा और उसे नोटिस की प्राप्ति से 60 दिन के भीतर आक्षेप, यदि कोई हो, दर्शाने के लिए कहा जाएगा।

परन्तु कलक्टर उक्त 60 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि भू-स्वामी विहित समय के भीतर युक्ति-युक्त कारणों से आक्षेप दाखिल करने से निवारित हुआ था, आक्षेप ग्रहण कर सकेगा।

(2) कलक्टर, यथास्थिति, भू-स्वामी या भू-स्वामियों को, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भू-स्वामियों को संदेय रकम अवधारित करते हुए, अधिनिर्णय देगा, और भू-स्वामियों के बीच रकम को प्रभाजित भी करेगा।

(3) जहाँ रकम अवयस्क को संदेय हो, वहाँ कलक्टर ऐसे इन्तजाम कर सकेगा, जो कि अवयस्क के हितों के बारे में साम्यपूर्ण हों।

रकम का संदाय। 7. धारा 6 के अधीन भू-स्वामी को संदेय रकम ऐसी रीति में ऐसी छ माही किस्तों में जो दस से ज्यादा न हो, जैसी विहित की जाएं, संदत्त की जाएगी।

राज्य सरकार में निहित भूमि का उपयोग। 8. (1) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार में निहित समस्त भूमि का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा :—

(क) ऐसा क्षेत्र जो इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित कुल क्षेत्र के पन्चास प्रतिशत से कम न हो, चरागाह और भू-सम्पदा के निवासियों के अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिए; और

(ख) शेष भूमि—

(i) भूमिहीन व्यक्ति या किसी अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटन के लिए; या

(ii) घर के निर्माण के लिए किसी विकलांग या गृहविहीन व्यक्ति को स्थल का आवंटन करने के लिए ;

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विरचित की जाने वाली स्कीम के अधीन और आवंटिती, उक्त स्कीम के अधीन उसे आवंटित भूमि पर प्रभार्य भू-राजस्व के अड़तालीस गुणा की दर से राशि और रेंट और उपकर, या तो एक मुश्त या छ माही किस्तों में जो चार से अधिक नहीं होगी, संदत्त करेगा।

(2) इस अधिनियम की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आरक्षित भूमि, ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाएं, सीमांकित की जाएगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विरचित किसी स्कीम में उन निबन्धनों और शर्तों का उपबन्ध किया जा सकेगा जिन पर भूमि का आवंटन किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में, परिवर्धन, उनके संशोधन, फेर-फार या प्रतिसंहरण कर सकेगी।

8-अ. अधिनियम की धारा 18 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अधिनियम के अधीन इसमें निहित भूमि के किसी क्षेत्र को, किसी व्यक्ति को पट्टे पर देकर या राज्य के विकास के हित में सरकार के किसी विभाग को अन्तरण द्वारा उपयोग कर सकेगी; यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के पर्याप्त कारण हैं और उप-धारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए भूमि, किसी भी दशा में, अधिनियम के अधीन सरकार में निहित भूमि के पच्चास प्रतिशत से कम नहीं होगी :

राज्य के विकास के लिए भूमि का उपयोग।

परन्तु जहां किसी व्यक्ति द्वारा भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए यह पट्टे पर दी गई है वहां पट्टा सभी विल्लंगमों से मुक्त समाप्त हो जाएगा और सरकार पट्टान्तरित परिसरों में पुनः प्रवेश करेगी और पट्टे का धन, यदि सरकार को संदत्त किया गया हो, सम्पूत कर दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति उस पर किए गए किसी सुधार और किसी निमित्त इमारत के लिए किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

9. इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के आदेश विरुद्ध अपील, राज्य सरकार को या उस द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आदेश के किए जाने से 60 दिन के भीतर की जाएगी।

अपील।

10. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यथा-स्थिति, कलक्टर द्वारा, राज्य सरकार या इसका द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश, किसी न्यायालय, या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिकारिता का वर्जन।

11. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी कार्यवाई के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के विरुद्ध न होगी।

विधिक कार्य-वाहियों का वर्जन।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन समस्त जांच और कार्यवाहियों में कलक्टर और किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां होंगी और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाएं।

प्रक्रिया।

13. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा :—

- (क) वे प्रखर और रीति जिसमें धारा 6 के अधीन नोटिस तामील किए जाएंगे ;
- (ख) किस्ते नियत करना और रीति जिसमें धारा 7 के अधीन रकम का संचाय किया जाएगा ;
- (ग) वह रीति, जिसमें धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन भूमि सीमांकित की जाएगी ;
- (घ) वह रीति और प्रक्रिया, जिसमें धारा 12 के अधीन जांच की जाएगी ;
- (ङ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन किसी नियम को बनाने की शक्ति, नियम क पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अधीन है ।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 7 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या सहमत हो जाए कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी हो गया या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति । 14. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो इसे कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

निरसन और व्यावृत्तियाँ । 15. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में लागू पंजाब शमलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का 18) निरसित हो जाएगा ।

(2) धारा 4 में यथा उपबन्धित के सिवाय, उपरोक्त अधिनियम का निरसन, तदधीन की गई किसी बात या कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा ।

(3) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई प्राधिकारी किन्हीं भी कार्यवाहियों में चाह, इस अधिनियम से पूर्व या पश्चात् संस्थित की गई हों, कोई भी ऐसा आदेश नहीं देगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो ।



हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलित भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1987  
(1987 का 10) का उद्धरण।

(4) व्यावृत्ति.—जहां मूल अधिनियम के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन की गई किसी भूमि का आवंटन, इस अधिनियम की धारा 2 और 3 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम में किए गए उपबन्धों से असंगत पाया जाता है, तब किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, भी इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए, ऐसे आवंटन को रद्द करना और इस प्रकार आवंटित भूमि का कब्जा लेना, वैध होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, प्रसन्नगत भूमि के आवंटिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

